

संख्या 11030/53/77-अआसी(11)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, 110001,

दिनांक 20 अप्रैल, 1978

सेवा में,

सभी राश्यों के महासचिवों को ।

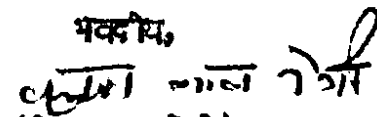
विषय :- भा0 प्र0 से0/भा0 पु0 से0 - वेतनमानों का संशोधन - वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन का बढ़ाया जाना और अगली वेतन वृद्धि की तारीख को परले रखा जाना - अनुपालन को जाने वाली प्रियाविधि से संबंधित अनुरोध ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 17-11-76 के पत्र संख्या 11030/22/76-अआसी(11) के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त पत्र के पैरा 2 में दिए गए अनुरोधों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार/विभागों से प्राधिकार मिलने पर संबंधित महासचिवों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन को बढ़ाया जाना चाहिए अथवा उनकी वेतनवृद्धि की अगली तारीख को उनके कनिष्ठ व्यक्तियों के वेतन वृद्धि की तारीख से पहले कर दिया जाना चाहिए । इस विभाग की जानकारी में यह बात लाई गई है कि कुछ राश्यों सरकारों ने अपने राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में हकदारों के कार्यों को उसी प्रकार अपने अधिकार में ले लिया है जिस प्रकार भारत सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ बिरो के माध्यम से राजपत्रित/अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों का कार्यालयीयों द्वारा आग्रह तथा वितरण को संशोधित प्रियाविधि को अपनाया है । ऐसे मामलों में, संबंधित महासचिवों द्वारा वेतन बढ़ाए जाने अथवा अगली वेतनवृद्धि की तारीख को पहले किए जाने का प्रश्न नहीं उठता । यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में संबंधित राज्य सरकार/विभागों से प्राधिकार प्राप्त होने पर ही संबंधित विभागीय प्राधिकारों/संबंधित वेतन तथा सेवा कार्यालय द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन को बढ़ाया जाना चाहिए अथवा अगली वेतनवृद्धि की तारीख को उनकी कनिष्ठों के वेतनवृद्धि की तारीख से पहले कर दिया जाना चाहिए ।

इसे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से जारी किया जाता है ।

भवदीय,


(श्री २२० नं०)

अवर सचिव, भारत सरकार ।